कीमतें और मुद्रास्फीति

04

अध्याय

देश में मुद्रास्फीति का 2017-18 के दौरान कम होना जारी रहा। अप्रैल-दिसंबर 2017-18 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति का औसत 3.3 प्रतिशत था, यह पिछले छह वित्तीय वर्ष में सबसे कम थी। खाद्य मुद्रास्फीति विशेषकर दालों और सब्जियों में बहुत अधिक कमी आने से सामान्य मुद्रास्फीति कम हुई। अप्रैल-दिसंबर 2017-18 के दौरान औसत खाद्य मुद्रास्फीति गिरकर 1.2 प्रतिशत पर आ गई। इस अवधि के दौरान मुख्य मुद्रास्फीति भी गिरी। वर्ष के दौरान ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बहुत से राज्यों में मुद्रास्फीति गिरावट देखी गई।

विषय प्रवेश

4.1 अर्थव्यवस्था में पिछले चार वर्षों में उच्च और अस्थिर मुद्रास्फीति से धीरे-धीरे स्थिर कीमतों की ओर पारगमन हुआ है। लगातार चौथे वर्ष के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक द्वारा मापी गई हेड लाइन मुद्रास्फीति नियंत्रण में है। वित्तीय वर्ष 2017-18 की शुरूआत 3.0 प्रतिशत वार्षिक मुद्रास्फीति दर से हुई। वित्तीय वर्ष 2017-18 की पहली दो तिमाहियों में कीमतों में सामान्य सी वृद्धि हुई थी, इसके परिणामस्वरूप पहली तिमाही में 2.2 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 3.0 प्रतिशत पर मुद्रास्फीति का स्तर नीचे रहा। हेड लाइन मुद्रास्फीति दर 2017 के जून महीने में 1.5 प्रतिशत पर अपनी श्रृंखला में कमतर आ गई। उपभोक्ता खाद्य कीमत सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति वित्तीय वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 1.2 प्रतिशत पर नीचे गिर गई।

4.2 थोक कीमत सूचकांक की नई श्रृंखला (2011-12) पर आधारित औसत मुद्रास्फीति 2016-17 में 1.7 प्रतिशत रही जबकि 2015-16 में (-)3.7 प्रतिशत और 2014-15 में 1.2 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) के लिए थोक कीमत सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 2.9 प्रतिशत रही। पिछले छह वर्षों के लिए कीमत सूचकांकों की प्रमुख श्रृंखलाओं पर आधारित मुद्रास्फीति सारणी-1 में दी गई है और अप्रैल 2014 से थोक कीमत सूचकांक और उपभोक्ता कीमत सूचकांक में उतार-चढ़ाव चित्र-1 में दिये गए हैं।

चित्र 1: विभिन्न सूचकांकों के अनुसार सामान्य मुद्रास्फीति (प्रतिशत)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (अप्रैल-दिसं.)*
डब्ल्यूपीआई	6.9	5.2	1.2	- 3.7	1.7	2.9 (P)
सीपीआई (समिश्र)	10.2	9.5	5.9	4.9	4.5	3.3 (P)
सीपीआई (आईडब्ल्यू)	10.4	9.7	6.3	5.6	4.1	2.3#
सीपीआई (एएल)	10.0	11.6	6.6	4.4	4.2	2.0#
सीपीआई (आरएल)	10.2	11.5	6.9	4.6	4.2	2.1#

स्रोत: थोक कीमत सूचकांक के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उपभोक्ता कीमत सूचकांक (समिश्र) के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय और सीपीआई (आईडब्ल्यू) सीपीआई (एएल) तथा सीपीआई (आरएल) के लिए श्रम ब्यूरो।

टिप्पणी: पुरानी श्रृंखला 2010=100 पर आधारित 2012-13 और 2014-15 के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक (समिश्र) मुद्रास्फीति।

पी-अनंतिम आईडब्ल्यू का अर्थ है औद्योगिक कामगार एएल का अर्थ है कृषि श्रमिक और आरएल का अर्थ है ग्रामीण श्रमिक।

#2017-18 (अप्रैल-नवंबर) की अवधि के लिए

*अप्रैल-दिसंबर 2017 के दौरान मुद्रास्फीति, अप्रैल-दिसंबर 2016 से नौ महिनों के लिए मासिक सूचकांक के औसत की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2017 से नौ महिनों के लिए मासिक सूचकांक के औसत में प्रतिशत परिवर्तन है।

चित्र 1: थोक कीमत सूचकांक और उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत)

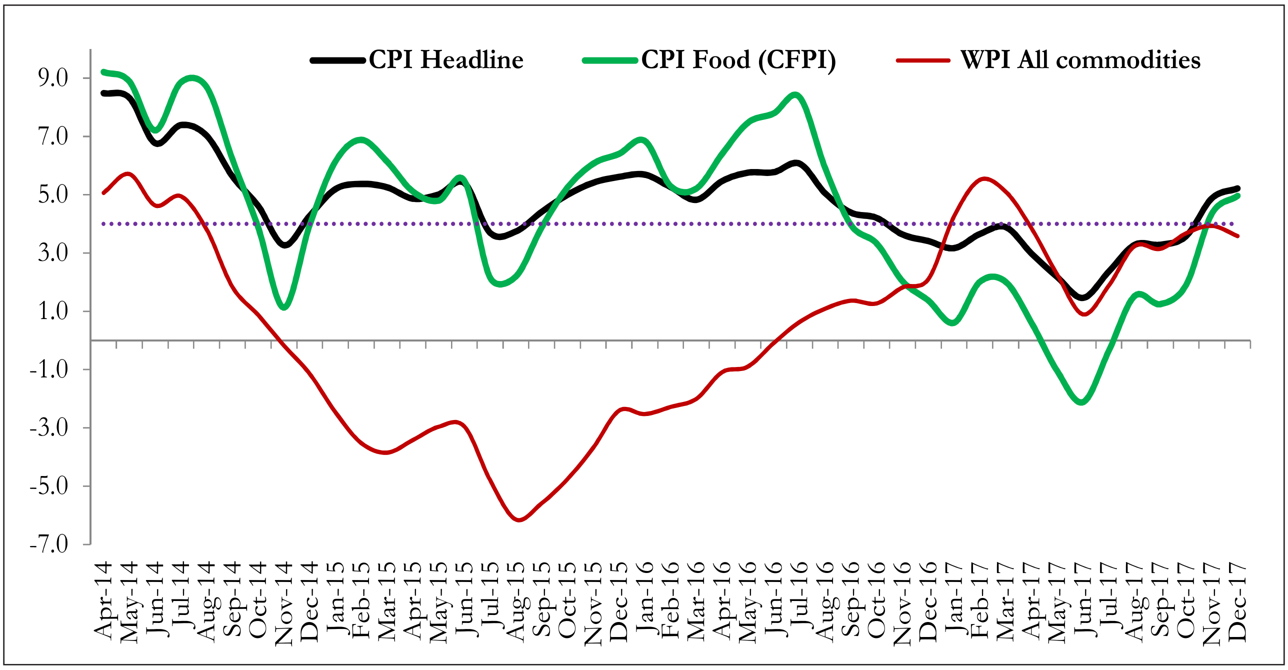

मुद्रास्फीति में वर्तमान प्रवृत्तियां

4.3 औसत सीपीआई (समिश्रित) मुद्रास्फीति 2014-15 में 5.9 प्रतिशत और 2015-16 में 4.9 प्रतिशत से कम होकर 2016-17 में 4.5 प्रतिशत हो गई थी। वित्त वर्ष 2017-18 में औसत मुद्रास्फीति (अप्रैल-दिसंबर) में 3.3 प्रतिशत थी, जो 4 प्रतिशत के आरंभिक स्तर से काफी कम थी। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में मुद्रास्फीति में गिरावट सौम्य, खाद्य मुद्रास्फीति संकेतक के कारण थी, जो-2.1 से 1.5 प्रतिशत के दायरे में रही। अक्तूबर 2017 तक सीधे 12 महीनों के लिए मुद्रास्फीति की दर 4 प्रतिशत से कम बनी रही (चित्र 1)। सीपीआई-समिश्र मुद्रास्फीति, दिसंबर 2016 में 3.4 प्रतिशत और नवंबर 2017 में 4.9 प्रतिशत की तुलना में दिसंबर माह 2017 के लिए 5.2 प्रतिशत थी।

4.4 खाद्य मुद्रास्फीति: सरकार के लगातार कीमतों पर नजर रखने के साथ-साथ अच्छे कृषि उत्पादन से मुद्रास्फीति, खास तौर से खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिली। उपभोक्ता खाद्य कीमत सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति 2014-15 में 6.4 प्रतिशत और 2015-16 में 4.9 प्रतिशत से कम होकर 2016-17 में 4.2 प्रतिशत हो गई थी। वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में औसत खाद्य मुद्रास्फीति कम होकर 1.2 प्रतिशत पर आ गई और दिसंबर 2017 में 5.0 प्रतिशत के स्तर पर रही। हाल के महीनों में खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि मुख्यत: सब्जियों और फलों की बढ़ती कीमतों के कारण है। हालांकि खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट के आधार व्यापक हैं, इसमें प्रमुख कारक हैं मांस एवं मछली, तेल एवं चर्बी, मसाले सब्जियां और दालें एवं उत्पाद। सीपीआई-समिश्र में 2.4 भारांश वाले दालें एवं उत्पाद उप-समूह में वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में (-) 22.1 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर्ज की गई थी जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 16.2 प्रतिशत मुद्रास्फीति दर्ज हुई थी। समग्र सीपीआई-सी में 6.04 भारांश वाली सब्जियों में 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 2.4 प्रतिशत मुद्रास्फीति दर्ज की गई।

4.5 थोक कीमत सूचकांक पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति में भी गिरावट आई। यह वित्त वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) में 6.3 प्रतिशत के मुकाबले वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में 2.3 प्रतिशत के स्तर पर थी। पिछले वित्त वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में खाद्य पदार्थों और खाद्य उत्पादों के थोक कीमत सूचकांक में भी गिरावट देखी गई है। डब्ल्यूपीआई खाद्य मुद्रास्फीति नवम्बर 2016 में 6.3 प्रतिशत और नवंबर 2017 में 4.1 प्रतिशत की तुलना में दिसंबर 2017 में 2.9 प्रतिशत थी।

सारणी 2: उपभोक्ता कीमत सूचकांक समिश्र के चुनिंदा समूहों में मुद्रास्फीति-आधार 2012 (प्रतिशत)

विवरण	भारांश	2016-17	2017-18 अप्रैल-दिसं.	दिसं.-16	नवं. 17	दिसं.-17 (पी)
सभी समूह	**100**	**4.5**	**3.3**	**3.4**	**4.9**	**5.2**
सीएफपीआई*	**39.1**	**4.2**	**1.2**	**1.4**	**4.4**	**5.0**
खाद्य एवं पेय पदार्थ	45.9	4.4	1.7	2.0	4.4	4.9
अनाज एवं उत्पाद	9.7	4.2	3.9	5.3	3.3	2.6
दूध एवं उत्पाद	6.6	4.1	4.2	4.4	4.3	4.4
सब्जियां	6.0	-2.2	2.4	-14.6	22.5	29.1
दालें एवं उत्पाद	2.4	9.3	-22.1	-1.6	-23.6	-23.5
ईंधन एवं प्रकाश	6.8	3.3	6.0	3.8	8.2	7.9
सीपीआई खाद्य एवं ईंधन समूह को छोड़कर (प्रमुख)	47.3	4.8	4.5	4.9	4.9	5.2

स्रोत: सीएसओ पी: अनंतिम *उपभोक्ता खाद्य कीमत सूचकांक

सारणी 3: थोक कीमत सूचकांक के चुनिंदा समूह में मुद्रास्फीति आधार 2011-12 (प्रतिशत)

विवरण	भारांश	2016-17	2017-18 अप्रै.-दिसं.	दिसं. 16	नवं.-17 (पी)	दिसं.-17 (पी)
सभी वस्तुएं	**100**	**1.7**	**2.9**	**2.1**	**3.9**	**3.6**
खाद्य सूचकांक	**24.4**	**5.8**	**2.3**	**3.6**	**4.1**	**2.9**
खाद्य वस्तुएं	15.3	4.0	2.3	0.1	6.1	4.7
अनाज	2.8	8.7	0.9	9.9	-2.1	-3.0
दालें	0.6	17.6	-27.5	14.8	-35.5	-34.6
सब्जियां	1.9	-5.3	19.3	-26.9	59.8	56.5
फल	1.6	6.0	3.6	0.6	4.2	12.0
खाद्य उत्पाद	9.1	9.5	2.3	10.7	0.5	-0.2
ईंधन एवं विद्युत	13.2	-0.2	9.7	4.2	8.8	9.2
खाद्य-भिन्न विनिर्मित उत्पाद (प्रमुख)	55.1	-0.1	2.6	1.0	3.0	3.2

स्रोत: डीआईपीपी पी: अंनतिम

4.6 मुख्य मुद्रास्फीति: जबकि हेडलाईन और खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है, पिछले चार वित्त वर्षों के दौरान सीपीआई आधारित मुख्य[1] मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से अधिक रही। हालांकि यह वित्त वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) में 4.8 प्रतिशत से कम होकर वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में 4.5 प्रतिशत रह गई और दिसंबर, 2017 में 5.2 प्रतिशत थी (चित्र 2)। वित्त वर्ष 2017-18 की शुरूआत से रिफाइन्ड कोर[2], कोर के बिलकुल आस-पास बढ़ रहा है, यह वित्त वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) में 5.0 से कम होकर वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में 4.4 प्रतिशत हो गया। रिफाइण्ड कोर की घट-बढ़ (आवास को छोड़कर)[3] रिफाइण्ड कोर की प्रवृत्तियां दर्शा रही हैं। तथापि, चालू वित्त वर्ष के दौरान 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बढ़े हुए मकान किराया भत्ते के क्रियान्वयन के बाद दोनों के बीच अन्तर बढ़ा है। रिफाइण्ड कोर (आवास को छोड़कर) वित्त वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) में 4.9 प्रतिशत से कम होकर वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में 4.0 प्रतिशत रह गया और नवम्बर 2017 में यह 4.3 प्रतिशत था।

1 सीपीआई में खाद्य एवं ईंधन समूह शामिल नहीं हैं।
2 सीपीआई खाद्य और ईंधन समूह, पेट्रोल एवं डीजल को छोड़कर।
3 सीपीआई खाद्य और ईंधन समूह, पेट्रोल एवं डीजल को छोड़कर।

चित्र 2: उपभोक्ता कीमत सूचकांक समिश्र आधारित मुख्य मुद्रास्फीति (प्रतिशत)

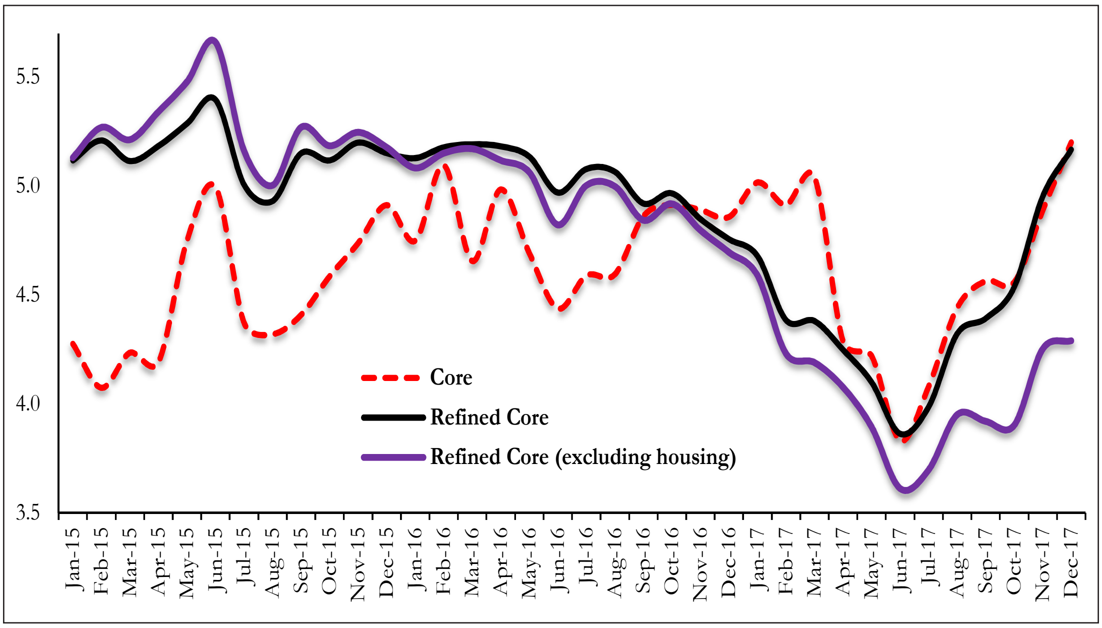

बॉक्स 4.1: उत्पादक कीमत सूचकांक

सरकार ने भारत में उत्पादक कीमत सूचकांक की रचना प्रारंभ करने के लिए कार्य विधियां सुझाने के लिए 21 अगस्त 2014 को प्रो. बी.एन. गोलदार की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया था। इस कार्यदल ने 31.08.2017 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। उत्पादक कीमत सूचकांक पर कार्यदल की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

(i) भारत में उत्पादक कीमत सूचकांक (पीपीआई) उच्चतर स्तर के भारांश के लिए सकल अंतिम प्रयोग कीमत का उपयोग करते हुए आपूर्ति उपयोग सारणी 2011-12 के आधार पर संकलित किया जा सकता है। आरंभ में वस्तुओं और सेवाओं के लिए सकल अंतिम प्रयोग भारांश पर आधारित सूचकाकों को अलग से संकलित किया जाना चाहिए। एक बार सेवा क्षेत्र के सूचकांक का कवरेज पर्याप्त ढंग से हो जाए और क्षेत्र-वार सूचकांक सुगठित और स्थिर हो पाएं, तब वस्तुओं और सेवाओं पर आधारित सकल सूचकांक सुदृढ़ और स्थिर हैं।
(ii) आदान पीपीआई के दो अलग-अलग समूह संकलित किए जा सकते हैं-एक समूह में सेवा सम्मिलित होगी और दूसरे में नहीं।
(iii) प्रयोक्ताओं के लाभार्थ अंतिम मांग और मध्यवर्ती मांग ढांचे पर आधारित उत्पाद या निर्गत पीपीआई का अतिरिक्त समूह भी संकलित किया जा सकता है।
(iv) उत्पादक कीमत सूचकांकों का संकलन शुरूआत में प्रायोगिक आधार पर किया जाए और इस के स्थिर होने तथा पणधारकों से सलाह-मशविरा करने के बाद ही थोक कीमत सूचकांक से उत्पादक कीमत सूचकांक प्रणाली की ओर अग्रसर होना चाहिए।
(v) प्रायोगिक तौर पर उत्पादक कीमत सूचकांक के संकलन के लिए थोक कीमत सूचकांक की मौजूदा श्रृंखला से एकत्रित दरों को उपयोग में लाया जाए।
(vi) प्रायोगिक उत्पाद कीमत सूचकांक माहवार जारी किए जाएंगे। शुरूआत में उत्पादक कीमत सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 होगा।
(vii) शुरूआती दौर में कार्य दल ने उत्पादक कीमत सूचकांक समूह में 15 सेवाओं को शामिल करने की सिफारिश की थी। उत्पाद कीमत सूचकांक के प्रायोगिक चरणों के दौरान सेवा क्षेत्र का विस्तार तात्कालिक आधार पर सभी प्रमुख क्षेत्रों पर कर दिया जाना चाहिए।
उत्पादक कीमत सूचकांक माल और सेवाओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को दर्शाता है। उनके उत्पादन स्थल से बाहर आने पर सूचक को उत्पादक कीमत सूचकांक की संज्ञा दी जाती है। दूसरी ओर जब वे उत्पादन प्रक्रिया में शामिल होते हैं, सूचक को आदान उत्पादक सूचकांक कहा जाता है। इस प्रकार उत्पादक उन सूचकांक कीमतों में औसत परिवर्तन दर्शाता है, जो उत्पादकों को प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार आदान सूचकांक उन कीमतों में औसत परिवर्तन को दर्शाता है, जो उत्पादक अपने आदानों के लिए भुगतान करते हैं। उत्पादक कीमत सूचकांक की तुलना अन्य पैमानों से, जैसे कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक से की जा सकती है जो खरीदारों अथवा उपभोक्ताओं की नजर से कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है।
थोक कीमत सूचकांक समूह सभी मध्यवर्ती और अंतिम उत्पादों की प्रथम अवस्था में थोक लेनदेन की कीमतों पर नजर रखता है। मध्यवर्ती और अंतिम उत्पादों के समुचित पृथक्कीकरण के बिना थोक कीमत सूचकांक के सकल समूह के आंकलन में अंतर्विष्ट ख़ामी यह है कि इसमें बहुगणना हो जाती है, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति के आकलन में गड़बड़ी हो सकती है। बहुगणना तब होती है, जब किसी पण्य विशेष की कीमत और इसके उत्पादन के लिए आदान, दोनों को सकल सूचकांक में शामिल कर लिया जाता है।
केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा संकलित आपूर्ति उपयोग सारिणी में से भार व्युत्पन्न करके बहुगणना करने से उत्पन्न विकृति को उत्पादक कीमत सूचकांक काफी हद तक कम करता है, इसके अलावा उत्पादक कीमत सूचकांक की परिधि में सेवाएं शामिल हैं, जो फिलहाल, थोक कीमत सूचकांक

के दायरे में नहीं आती। थोक कीमत सूचकांक से उत्पादक कीमत सूचकांक की ओर अग्रेषित करने के फायदे हैं: सभी माल एवं सेवाओं के थोक लेनदेन को शामिल करना, थोक कीमत सूचकांक में अंतर्निहित दो बार गणना की प्रवृत्ति को समाप्त करना और सूचकांकों का संकलन, जो अपस्फायक के रूप में प्रयोग करने के लिए वैचारिक रूप से राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीय के अनुकूल हो।

कार्य दल की पूरी रिपोर्ट आर्थिक सलाहकार कार्यालय की वेबसाइट http://eaindustry.nic.in/pp/-final-report.pdj. पर देखी जा सकती है।

मुद्रास्फीति के कारक

4.7 अखिल भारत स्तर पर वित्तीय वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान उपभोक्ता कीमत सूचकांक सम्मिश्रित मुद्रास्फीति मुख्यत: खाद्यान्नों के कारण हुई। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) (चित्र-3) के दौरान विविध[4] समूह ने इसको बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया। जैसाकि चित्र 6 से देखा जा सकता है, वस्तु मुद्रास्फीति (उपभोक्ता कीमत सूचकांक-मिश्रित में 76.6% का भारांश) जून, 2017 से बढ़ रहा है, जबकि सेवाओं में मुद्रास्फीति (23.4% के भारांश सहित) लगभग 5% रही। 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) की तुलना में 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में आवास समूह ने मुद्रास्फीति में दो गुना योगदान किया। आवास को छोड़कर सेवा क्षेत्र में मुद्रास्फीति 2017-18 में पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5% से कम होकर 3.8% हो गई। 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) की तुलना में 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में ईंधन और बिजली समूह के उपभोक्ता कीमत सूचकांक मुद्रास्फीति में योगदान में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई।

4.8 यद्यपि 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) में खाद्य उपभोक्ता कीमत सूचकांक (ग्रामीण) मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण था, मौजूदा वित्तीय वर्ष के अप्रैल-दिसंबर अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 'विविध समूह' ने मुद्रास्फीति को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ईंधन, बिजली, कपड़ा, जूते/चप्पल और पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ समूह में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-दिसंबर, 2017 में उपभोक्ता कीमत सूचकांक (ग्रामीण) मुद्रास्फीति में उछाल आया (चित्र 4 देखें)।

4.9 शहरी क्षेत्रों में पिछले वर्ष अप्रैल-दिसंबर की अवधि के दौरान मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण खाद्यान्न था, लेकिन आवास क्षेत्र ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में अप्रैल-दिसंबर की अवधि के दौरान उपभोक्ता कीमत सूचकांक (शहरी) मुद्रास्फीति में सबसे ज्यादा योगदान दिया, इसके बाद विविध समूह का योगदान रहा (चित्र 5 देखें)।

चित्र 3: 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) और 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) उपभोक्ता कीमत सूचकांक (मिश्रित) मुद्रास्फीति में योगदान

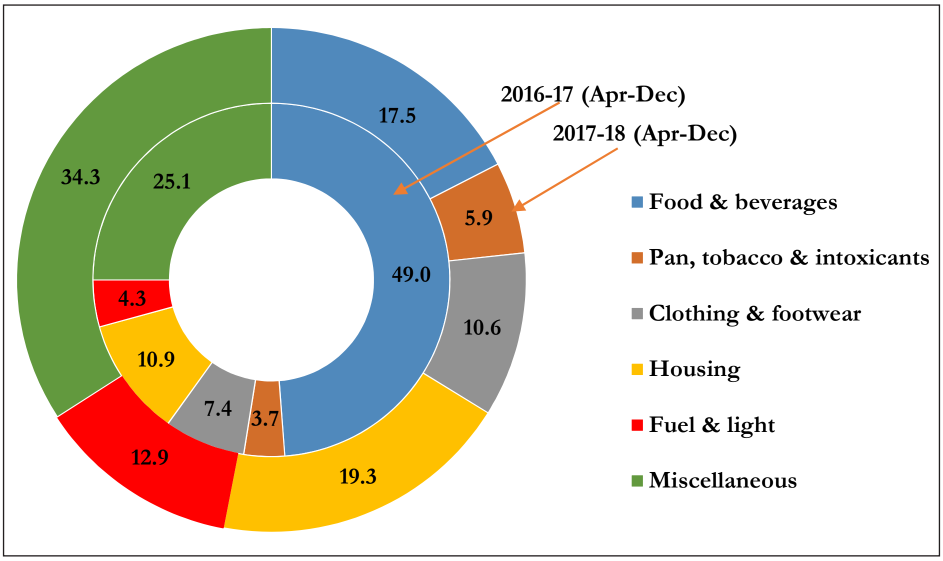

[4] विविध समूह (सीपीआइ-सी में 28.32%) के भारांश, में घरेलू वस्तुएं एवं सेवाए, स्वास्थ्य यातायात एवं संचार, मनोरंजन एवं मनोविनोद, शिक्षा और निजी देखभाल और प्रभाव।

चित्र-4: 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) और 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में उपभोक्ता कीमत सूचकांक (ग्रामीण) मुद्रास्फीति में योगदान

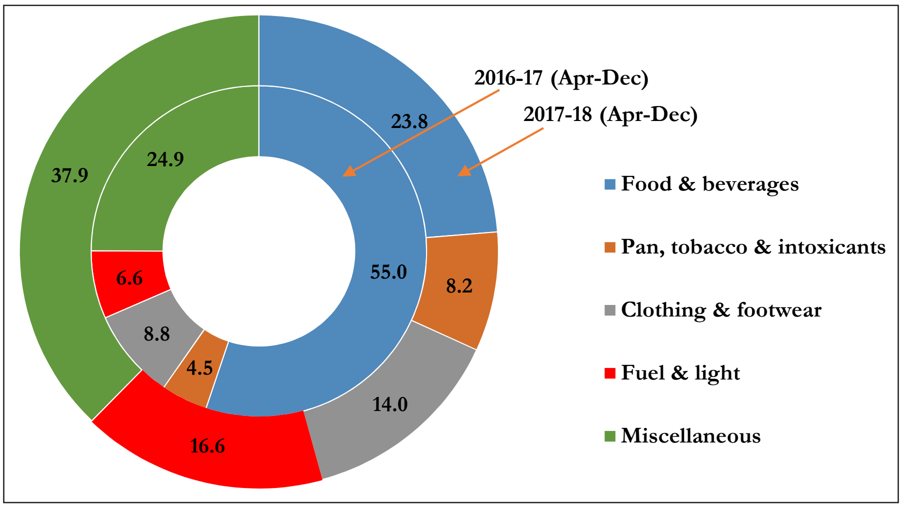

चित्र-5: 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) और 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में उपभोक्ता कीमत सूचकांक (शहरी)

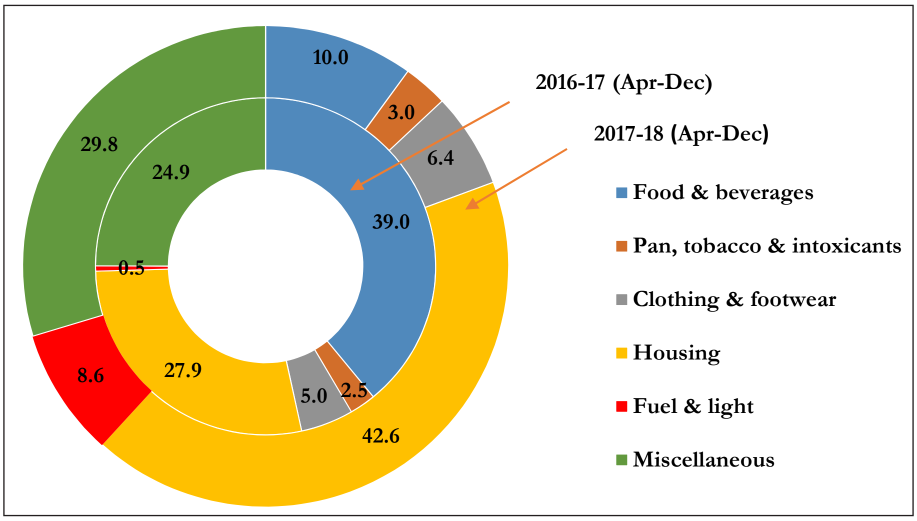

चित्र-6: माल और सेवाओं में उपभोक्ता कीमत सूचकांक मुद्रास्फीति (प्रतिशत)

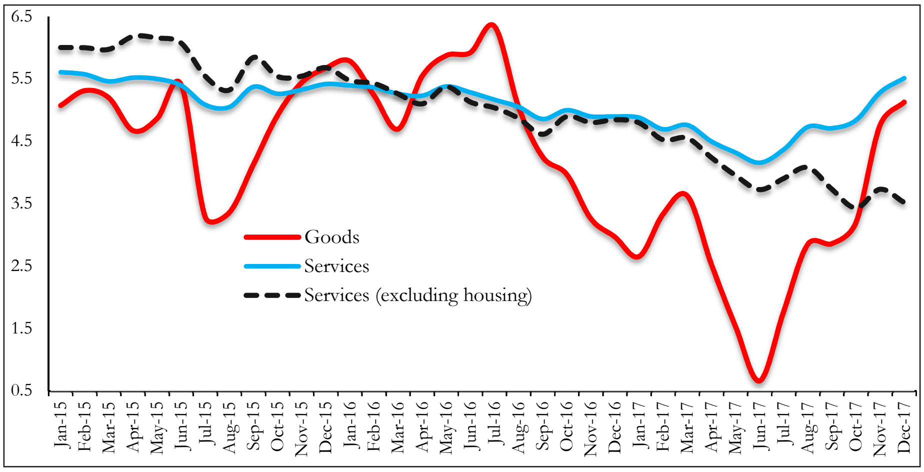

बॉक्स-4.2 : आवास कीमत सूचकांक

एक भौगोलिक सीमा के भीतर रिहायशी संपत्ति की कीमतों में उतार/चढ़ाव को मापने के लिए आवास कीमत सूचकांक एक व्यापक उपाय है। देश में प्रथम सरकारी आवासीय कीमत सूचकांक, जिसे ''एनएचबी-रेसिडेक्स'' की संज्ञा दी गई, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा जुलाई 2007 में शुरू किया गया। कुछ समय बाद आधार वर्ष बदल कर वित्तीय वर्ष 2012-13 कर दिया गया ताकि अद्यतन सूचना प्राप्त हो सके और देश में मौजूदा आर्थिक स्थिति की वास्तविक छवि पेश की जा सके। इस समय राष्ट्रीय आवास बैंक वित्तीय वर्ष 2012-13 को आधार वर्ष मानकर 50 शहरों के लिए त्रैमासिक एनएचबी रेसिडेक्स प्रकाशित कर रहा है। इन 50 शहरों में 18 राज्य/केंद्र शासित क्षेत्रों की राजधानियां तथा 37 स्मार्ट सिटी शामिल हैं। इस समय राष्ट्रीय आवास बैंक समेकित अखिल भारत आवास कीमत सूचकांक की गणना नहीं कर रहा है।

एनएचबी अभी तक समग्र स्तर पर अखिल भारतीय आवास कीमत सूचकों का आंकलन नहीं कर रहा। हमने आन्तरिक प्रयोग के लिए शहरी सूचकों की जनसंख्या भारित औसत का आंकलन कर उसे अखिल भारतीय सूचक माना है (चित्र 1)। चित्र से पता चलता है कि अखिल भारतीय स्तर पर मकानों की कीमतों में वृद्धि दर दिसंबर, 2016 को समाप्त तिमाही से घटना शुरू हो गई थी। यह वित्तीय वर्ष 2016-17 की तीसरी तिमाही में 8% से घटकर वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही में लगभग 4% हो गई है।

चित्र-1: आकलन कीमतों पर राष्ट्रीय आवास बैंक, आवास कीमत सूचकांक पर आधारित आवास कीमत सूचकांक (प्रतिशत)

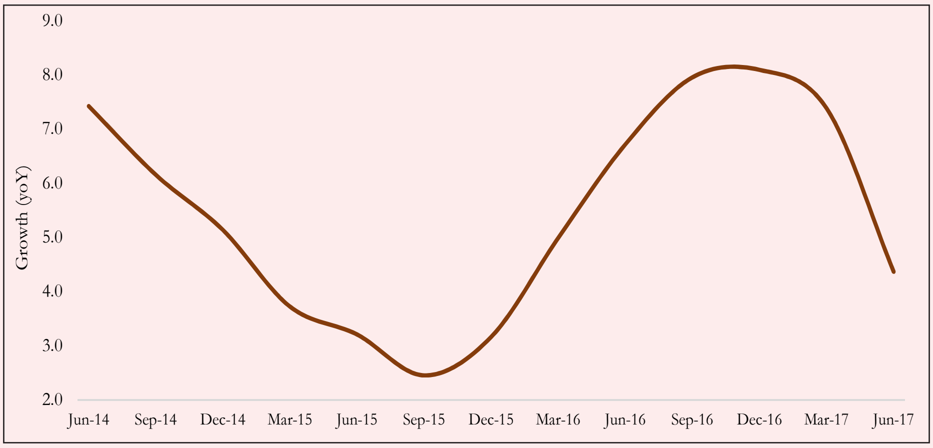

(टिप्पणी): राष्ट्रीय आवास बैंक बैंकों/आवासीय वित्तीय निगमों से तिमाही आधार पर प्राप्त कीमतांकन डाटा के मद्देनजर प्रत्येक 50 शहरों के आवास कीमत सूचकांकों की गणना करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुंबई शहर के लिए (आधार 2002-03=100) तिमाही आवास कीमत सूचकांक के साथ 2007 में आवास कीमत सूच. कांक का संकलन शुरू किया। तबसे इसने अपना कार्य-क्षेत्र 9 और शहरों तक विस्तारित किया है, अपने आधार को बदल कर 2010-11=100 किया है और तिमाही मिश्रित अखिल भारत आवास कीमत सूचकांक प्रकाशित करना शुरू किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक का तिमाही आवास कीमत सूचकांक दस प्रमुख शहरों में आवास पंजीकरण प्राधिकारियों से प्राप्त लेन देन के आंकड़ों पर आधारित है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के अखिल भारत आवास कीमत सूचकांक के अनुसार मकानों की कीमतों में वृद्धि मार्च, 2016 को समाप्त तिमाही में 3% के न्यून स्तर पर रही किन्तु इस में कुछ उतार-चढ़ाव के साथ उछाल आया है। 2017-18 की प्रथम तिमाही (चित्र 8) में यह बढ़कर 8.7% हो गयी। (चित्र 2)

चित्र 2 : आरबीआई के अखिल भारतीय एचपीआई पर आधारित एचपीआई मुद्रास्फीति

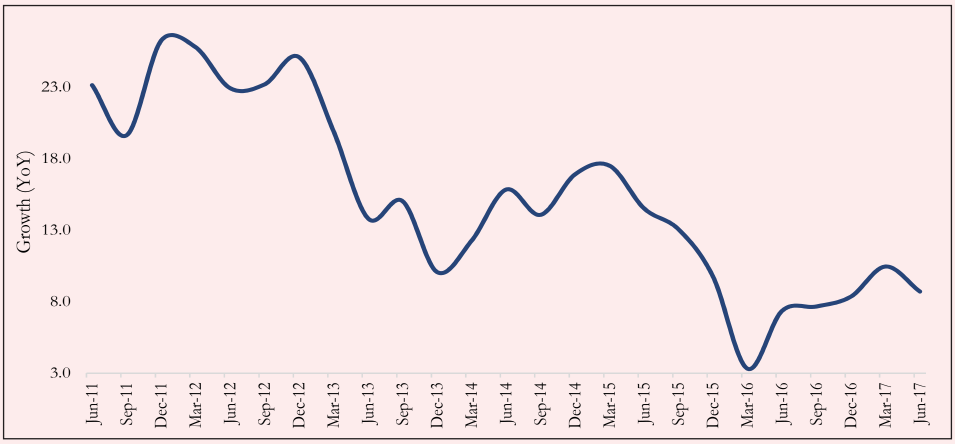

राज्यवार[5] मुद्रास्फीति

4.10 वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान अधिकतर राज्यों में उपभोक्ता कीमत सूचकांक मुद्रास्फीति में तेजी से कमी देखने को मिली है (चित्र 7)। वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में सत्रह राज्यों में मुद्रास्फीति 4% से कम थी जबकि वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर में) केवल तीन राज्यों में ऐसी स्थिति थी। पांच राज्यों नामत: जम्मू और कश्मीर, केरल, दिल्ली, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में 4 प्रतिशत से अधिक मुद्रास्फीति दर्ज की गई जबकि उन्नीस राज्यों में वित्त वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) में मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से अधिक थी। दस राज्यों की मुद्रास्फीति दर वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) की अखिल भारतीय औसत दर से कम थी, जिनमें ओडिशा की मुद्रा स्फीति दर सबसे कम थी और इसके बाद क्रमश: उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार की मुद्रास्फीति दर थी।

4.11 पन्द्रह राज्यों के शहरी क्षेत्रों में वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में मुद्रास्फीति दर 4 प्रतिशत से कम थी जबकि वित्त वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) में यह स्थिति बारह राज्यों में ही थी (चित्र 8)। उपभोक्ता कीमत सूचकांक-ग्रामीण के मामले में वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में पन्द्रह राज्यों की मुद्रास्फीति दर 4 प्रतिशत से कम थी, जबकि वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) में यह केवल एक राज्य इस स्तर से कम रही थी (चित्र 9)।

चित्र 7: उपभोक्ता कीमत सूचकांक (समिश्र) राज्यों की सामान्य मुद्रास्फीति (प्रतिशत)

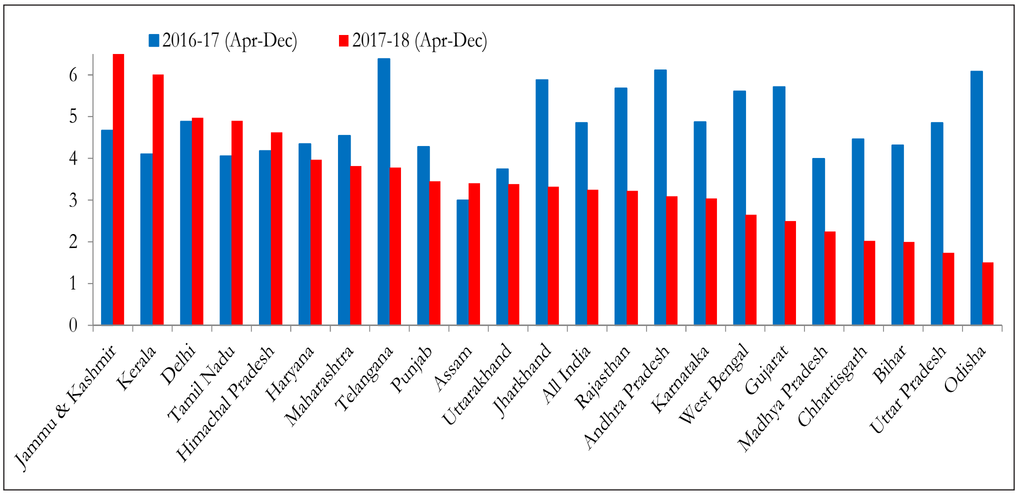

चित्र 8: उपभोक्ता कीमत सूचकांक (शहरी) राज्यों की सामान्य मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

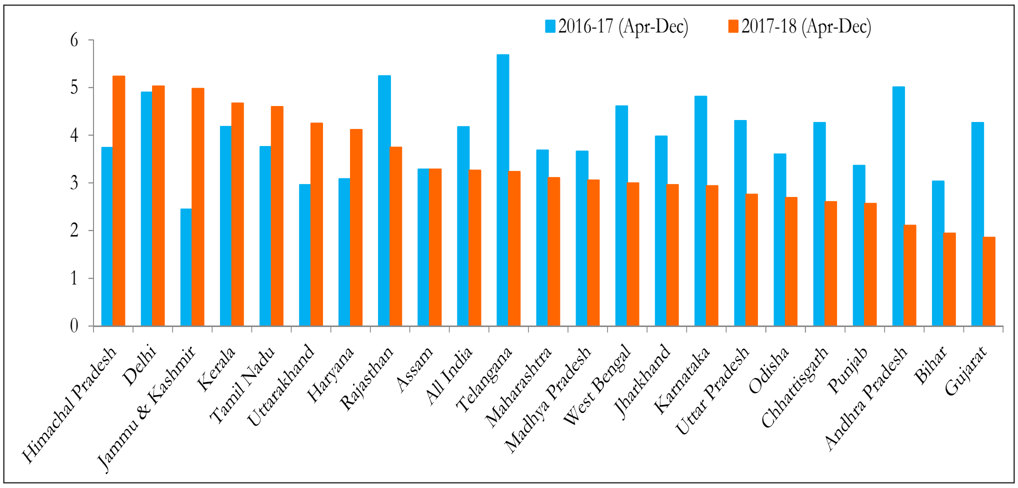

5. विश्लेषण दिल्ली सहित 22 राज्यों तक सीमित है

6. अप्रैल से दिसंबर 2017 के दौरान मुद्रास्फीति अप्रैल से दिसंबर 2016 तक नो महीनों के औसत मासिक सूचकांक की तुलना में अप्रैल से दिसंबर 2017 तक नो महीनों औसत मासिक सूचकांक में प्रतिशतांक परिवर्तन है।

चित्र 9: उपभोक्ता कीमत सूचकांक (ग्रामीण) राज्यों की सामान्य मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

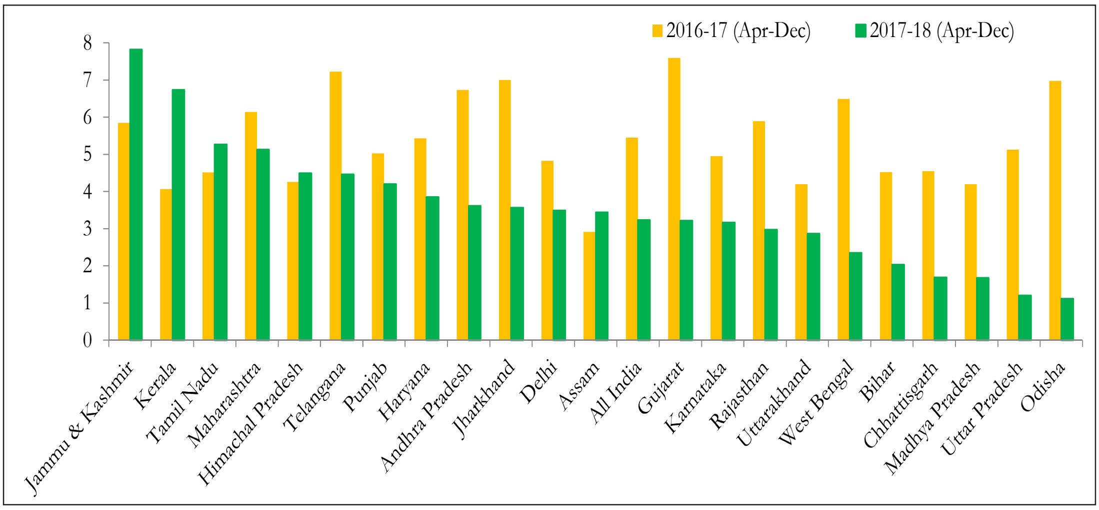

बाक्स-4.3: उपभोक्ता कीमत सूचकांक-समिश्र और इसके खाद्य घटकों में मौसमी उच्चावचन

वर्ष के दौरान कभी-कभी आपूर्ति की कमी होने से वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को मौसमी प्रकृति का माना जाता है। सामान्य (शीर्षक) मुद्रास्फीति स्थायी (कोर) की तुलना में अधिक अस्थिर होती है; आपूर्ति में कमी के कारण प्रभावित होने वाली खाद्य पदार्थों की सापेक्ष कीमत में बड़ा परिवर्तन होने के कारण इसमें घट-बढ़ होती है। खाद्य समूह, जिसका भारत में कीमत सूचकाक की श्रृंखला (विशेषकर उपभोक्ता कीमत सूचकांक) में विशेष महत्व होता है, पर भी मौसम का प्रभाव पड़ता है। कीमत सूचकांक की श्रृंखला में, विशेषकर दालों, फल और सब्जियों के समूह में उनकी मौसमी प्रकृति के कारण काफी परिवर्तन देखने को मिले हैं।

कीमत श्रृंखला की मौसमी प्रकृति की जांच के लिए प्रयास किया गया है ताकि मौसमी कारकों की सीमा और प्रकृति का आकलन किया जा सके। यह विश्लेषण, भारतीय रिजर्व बैंक की आंतरिक तकनीकी समूह की रिपोर्ट में अपनाए गए दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है। X-12 'अरीमा' पद्धति का प्रयोग कर कीमत श्रृंखला के मौसमी कारक प्राप्त किए जाते हैं। 1.00 से अधिक के मौसमी कारकों से उस अवधि की जानकारी मिलती है जब मौसमी कारणों से कुछ उर्ध्वमुखी परिवर्तन नजर आने की संभावना रहती है।

चित्र 1 से 3 क्रमशः उपभोक्ता कीमत सूचकांक-समिश्र के हेडलाइन, खाद्य समूह और सब्जी समूह के मौसमी कारक दर्शाते हैं। ये उपभोक्ता कीमत सूचकांक-समिश्र (सभी समूह) के लिए जुलाई से शुरू होकर नवम्बर माह के अंत तक की मौसम की प्रकृति को दर्शाते हैं। सीएफपीआई और सब्जियों के लिए अगस्त माह में मौसमी कारक की अधिकतम सीमा देखने को मिलती है उपभोक्ता कीमत सूचकांक-समिश्र के खाद्य समूहों में मौसमी प्रकृति की मौजूदगी के विपरीत, इसके गैर-खाद्य समूहों में नगण्य मौसमी प्रकृति देखने को मिलती है।

चित्र 1: उपभोक्ता कीमत सूचकांक-समिश्र सभी समूहों के मौसमी कारकों का उच्चावचन

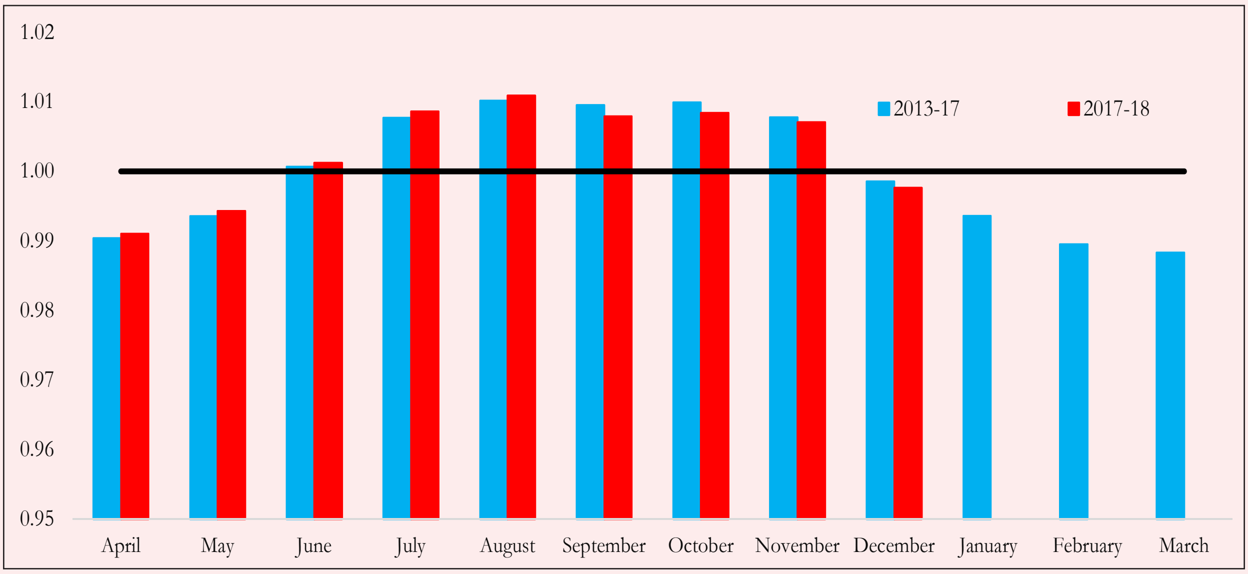

चित्र 2: सीएफपीआई के मौसमी कारकों का संचलन

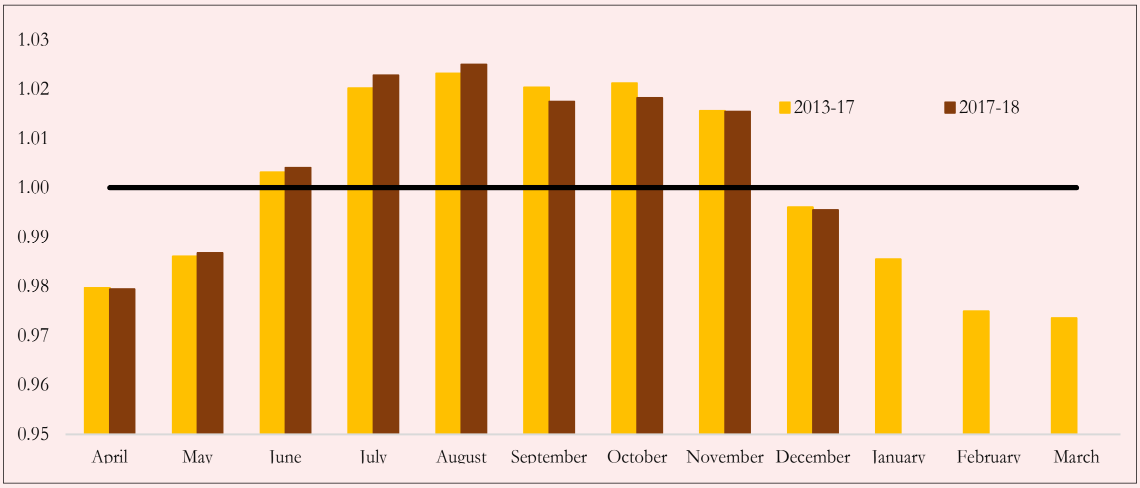

चित्र 3: उपभोक्ता कीमत सूचकांक-समिश्र सब्जियों के मौसमी कारकों का संचलन

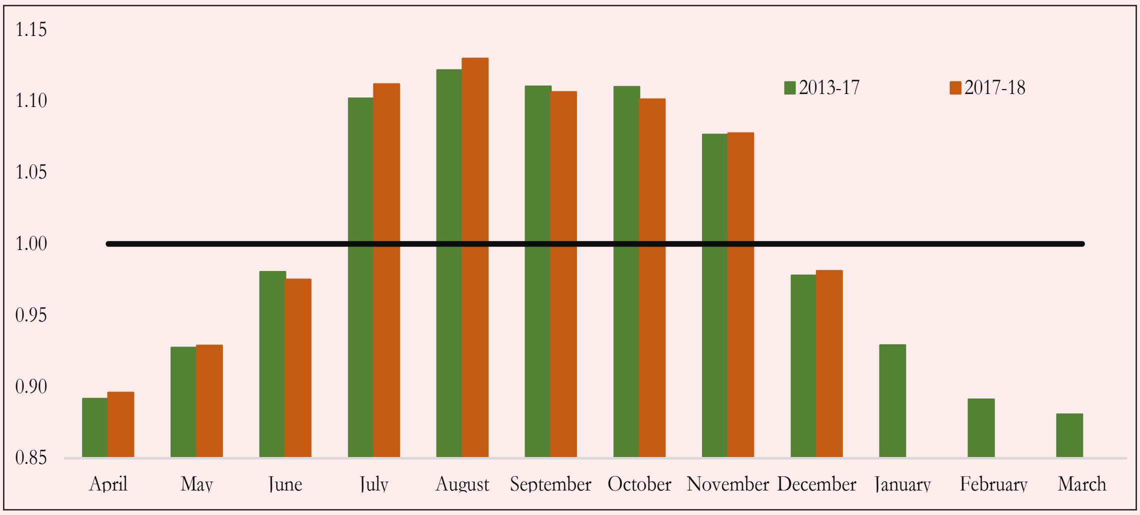

किसी वर्ष विशेष और बाद के वर्षों के दौरान कीमत श्रृंखला में मौसमी कारकों की भिन्नता को देखने के लिए चार वर्षों अर्थात 2013-14 से 2016-17 की कीमत श्रृंखला के मौसमी कारकों के लिए विचलन के गुणांक (सीवी) की गणना की जाती है। सारणी 1 से स्पष्ट है कि मौसमी कारकों की भिन्नता का स्तर सामान्य कीमत श्रृंखला की अपेक्षा खाद्यान्न के मामले में अधिक है। खाद्य कीमत श्रृंखला के भीतर सब्जियों का विचलन स्तर, दालों की भिन्नता स्तर से कई गुना अधिक होता है। इस अवधि के दौरान दालों के मौसमी कारकों के विचलन गुणांक (सीवी) में वृद्धि हुई है।

सारणी 1: उपभोक्ता कीमत सूचकांक-समिश्र के प्रमुख समूहों/उप समूहों के लिए विचलन गुणांक

	सीपीआई.सी सभी समूह	सीएफपीआई	सीपीआई.सी (दालें एवं उत्पाद)	सीपीआई.सी (सब्जियां)	सीपीआई.सी (गैर सीएफपीआई)
2013-14	0.90	1.96	1.29	9.68	0.26
2014-15	0.88	1.97	1.50	9.68	0.20
2015-16	0.86	1.96	1.71	9.81	0.14
2016-17	0.84	1.95	1.90	9.82	0.11

स्रोत: सर्वेक्षण परिकलन

*मुद्रास्फीति में मौसमी उतार-चढ़ाव पर आंतरिक तकनीकीय समूह, भा.रि.बैं. की रिपोर्ट मार्च 2008

वैश्विक वस्तु कीमतों के रूझान

4.12 विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित वस्तु कीमतों के अनुसार ऊर्जा से जुड़ी वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। इनमें वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) 15.3 प्र. तिशत की औसत वृद्धि दर्ज की गई जबकि वित्त वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) में यह (-) 8.0 प्रतिशत थी (चित्र 10)। अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक पर आधारित ''ईंधन और ऊर्जा'' की मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव विश्व बैंक ऊर्जा कीमत सूचकांक का अनुगमन करता है और यह वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में 9.7 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ा है जबकि वित्त वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान यह वृद्धि (-) 6.5 प्रतिशत थी (चित्र 11)। वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में विश्व बैंक खाद्य कीमतों में 3.0 प्रतिशत की कमी हुई परंतु पिछले वर्ष की समनुरूपी अवधि में इनमें 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसके विपरीत एफएओ की खाद्य कीमतों में वित्त वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) के 3.2 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में 5.8 प्रतिशत की उच्च मुद्रास्फीति दर्ज की गई। डब्ल्यूपीआई की बेस मेटल आधारित धातुओं की कीमतों ने भी विश्व बैंक के 'बेस मेटल' कीमत का अनुगमन किया है, हालांकि वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान विश्व बैंक की 'बेस मेटल' मुद्रास्फीति की 23.7 प्रतिशत की तुलना में डब्ल्यूपीआई के अनुसार 'बेसिक मेटल' की मुद्रास्फीति दर कम हो कर 9.9 प्रतिशत रह गई है।

चित्र 10: विश्व बैंक कीमत सूचकांक तथा एफएफपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत)

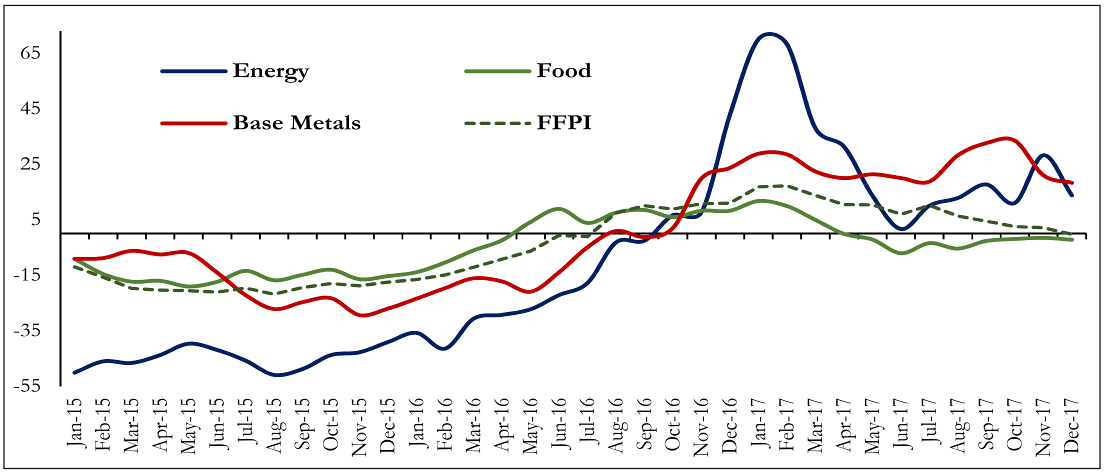

चित्र 11: थोक कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति (प्रतिशत)

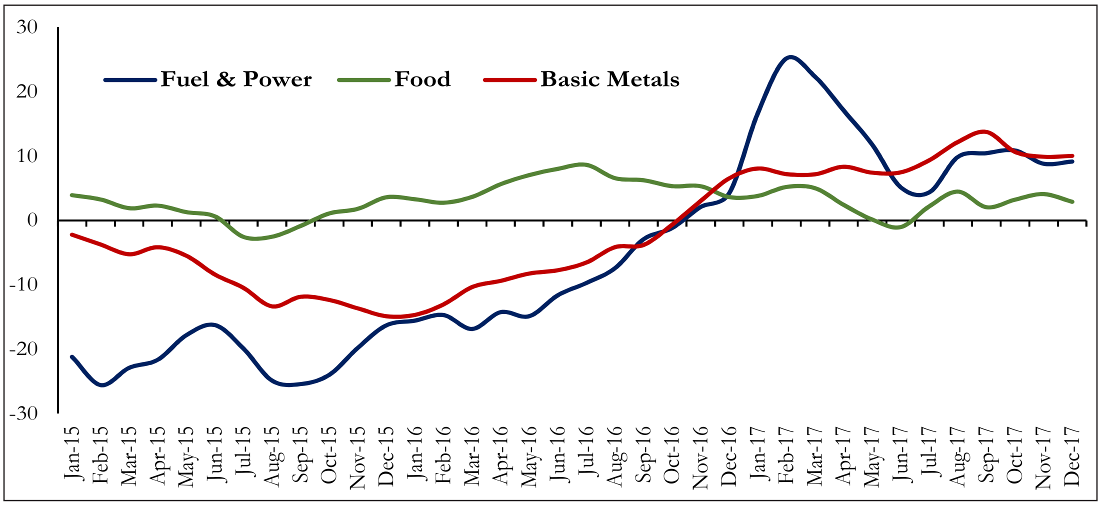

7 एफएफपीआई-एफएओ खाद्यान्न कीमत सूचकांक/एफएओ (खाद्य और कृषि संगठन) खाद्य कीमत सूचकांक खाद्य वस्तुओं की श्रृंखला की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन का पैमाना है) इसमें पांच वस्तु समूह कीमत श्रृंखला के औसत शामिल होती है जो वर्ष 2002-2004 के लिए प्रत्येक समूह के औसत निर्यात हिस्सों से भारित होता है।

मुद्रास्फीति रोकने के लिए प्रयास

4.13 केन्द्रीय सरकार नियमित आधार पर कीमतों की स्थिति पर नजर रखती है क्योंकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना प्राथमिकता का क्षेत्र है। मुद्रास्फीति, विशेषकर खाद्यान्न मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- आवश्यक होने पर, जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, आवश्यक वस्तु अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा कम आपूर्ति वाली वस्तुओं के लिए कालाबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु अनुरूप अधिनियम, 1980 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकारों के परामर्शिकाएं जारी की जा रही हैं।
- कीमत और उपलब्धता स्तर के संबंध में शीर्षस्थ स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। ये बैठकें सचिवों की समिति, अंतर मंत्रालयी समिति, कीमत स्थिरीकरण निधि प्रबंधक समिति तथा अन्य विभागीय स्तर की समीक्षा बैठकों के स्तर पर की जाती है।
- खाद्य पदार्थों के लिए अधिकतम समर्थन कीमतें (एमएसपी) घोषित की गई हैं ताकि उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके और ऐसा कर खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाई जा सके जिससे कीमतें कम करने में मदद मिलेगी।
- दाल, प्याज आदि जैसी कृषि वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए कीमत स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) नामक योजनागत स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- सरकार ने दालों के सुरक्षित भंडार (बफर स्टाक) को 1.5 लाख मी॰ टन से बढ़ाकर 20 लाख मी0 टन करने को अनुमोदित कर दिया है ताकि खुदरा कीमतों को न बढ़ने देने के लिए कारगर बाजारी हस्तक्षेप किया जा सके। तद्नुसार घरेलू खरीद तथा आयात के मध्यम से कीमत स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) के अंतर्गत दालों का 20 लाख टन तक का गतिशील सुरक्षित भंड़ार तैयार किया गया है इसमें से 3.26 लाख मी॰ टन, बाजारी हस्क्षेप तथा बफर प्रबंधक के लिए बाजार में उतारा गया है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने, मध्याह्न भोजन योजना आदि के लिए सुरक्षित भंडार से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दालें दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त सेना तथा केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों की दाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी सुरक्षित भंडार की दालों का उपयोग किया जा रहा है। हाल ही में यह निर्णय भी लिया गया है कि वे सभी मंत्रालय/विभाग अपने कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सुरक्षित भंडार की दालों का उपयोग करेंगे जिनकी पोषण घटक से जुड़ी योजनाएं या भोजन उपलब्ध करवाने/कैटरिंग (खान-पान)/अतिथ्य सरकार सेवा से जुड़ी योजनाए चल रही हैं।
- खाद्य तेलों के निर्यात की अनुमति केवल 5 किलों के ब्रॉडयुक्त कंज्यूमर पैक में दी गई थी जिसकी न्यूनतम निर्यात कीमत 900 रु॰ प्रति मी॰ टन अमेरिका डालर रखा गया था। घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए खजूर के तेल, सरसों के तेल और सूरजमुखी के तेल को छोड़कर तेल के निर्यात से यह प्रतिबंध हटा लिया गया है।
- सरकार ने अप्रैल, 2018 तक चीनी के स्टाक्स्टिों/डीलरों पर स्टॉक होल्डिग की सीमा तय कर दी है।
- सरकार ने चीनी के निर्यात पर 20% उत्पाद शुल्क लगाया ताकि उपलब्धता को बढ़ाया जा सके और बढ़ती कीमत को कम किया जा सके।
- शून्य सीमा शुल्क पर 5 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी गई, इसके बाद 25% सीमा शुल्क पर अतिरिक्त 3 लाख टन के आयात की अनुमति प्रदान की गई।
- सभी प्रकार के प्याज के निर्यात की अनुमति साख-पत्र पर दी जाएगी जो 31 दिसंबर, 2017 तक 850 प्रति मी॰ टन न्यूनतम निर्यात कीमत (एमईपी) के अधीन होगा।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्याज की भंडार सीमा (स्टॉक सीमा) तय करने की सलाह दी गई है। राज्यों से अनुरोध किया गया था कि अपनी प्याज की मांग के बारे में सूचित करें ताकि उपलब्धता बढ़ाने और मौजूदा ऊंची दर में कमी लाने के लिए आवश्यक मात्र में आयात की कार्रवाई शुरू की जा सके।

निष्कर्ष

4.14 आवास एवं ईंधन तथा प्रकाश समूह को छोड़कर सभी बड़ी वस्तु समूहों में मुद्रास्फीति में व्यापक कमी आने से वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान उपभोक्ता कीमत सूचकांक मुद्रास्फीति में 3.3 प्रतिशत रह गई। नवम्बर 2016 से अक्तूबर 2017 तक 12 माह तक मुख्य मुद्रास्फीति (हेडलाइन इनफ्लेशन) 4 प्रतिशत से कम रही है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-दिसंबर के दौरान उपभोक्ता कीमत सूचकांक खाद्य मुद्रास्फीति औसतन एक प्रतिशत के आस-पास रही है।